शटल यात्रियों से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं मोदी जी

फ़रीदाबाद (म.मो.) कोरोना के नाम पर पूरे देश में अचानक तालाबंदी की घोषणा करके मोदी ने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर डाला था। उसके बाद तालाबंदी खोलने के नाम पर जो ड्रामेबाज़ी मोदी सरकार ने की वह भी गजब की जनविरोधी रही। देश भर में आवागमन खोलने के नाम पर सबसे पहले हवाई यात्रा व महंगी ट्रेनों को चलाया गया। मुसीबतों के मारे जो गरीब यात्री साधारण ट्रेनों से यात्रा करने में सक्षम थे उन्हें यात्रा से वंचित रखने के लिये महंगी वातानुकूलित ट्रेनें चलाई गयी। इनके भाड़े हवाई यात्रा के समान रहे। उधर हवाई जहाज चलाने वाली कम्पनियों ने भी मौके पर फ़ायदा उठा कर खूब मनमानी लूट मचाई। जनता को काफ़ी तड़पाने के बाद थोड़ी-थोड़ी बस सेवा शुरू की गयी जो आज खबर लिखते समय तक भी आधी अधूरी है जो मैट्रो रेल सेवा एनसीआर में परिवहन सेवा की जान कही जाती है उसे भी बहुत मुश्किल से रो-पीट कर सितम्बर माह में यानी साढे पांच माह बाद चालू किया गया। लेकिन एनसीआर की सबसे पुरानी, सुलभ एवं सस्ती सवारी, रेलवे की शटल सेवा को अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

विदित है कि यूपी के कोसी, मेरठ, हरियाणा के पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी व होडल आदि से लाखों लोग रेलवे की शटल सेवा से यात्रा करते हैं जिन्हें हर रोज़ रोज़ी-रोजगार के लिये दिल्ली से आवागमन करना पड़ता है। इन सभी दैनिक यात्रियों ने एमएसटी (मंथली सीजन टिकट) बनवाये होते हैं। इन लोगों के लिये मेट्रो या बसों से यात्रा करना अत्यधिक महंगा पड़ता है। महंगाई, काम छूटने व वेतन कटौती के चलते इन लोगों के सामने मोदी सरकार ने भयंकर संकट खड़ा करके रख दिया है।

दरअसल बीते 6 साल का अनुभव बताता है कि मोदी सरकार ने रेलवे जैसे, दुनिया के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्क का सत्यानाश करने की ठान रखी है। इस नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने वाले चार लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। राष्ट्रीय तालाबंदी से पूर्व भी रेलवे की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इसकी सबसे अधिक मार शटल सेवा पर ही पड़ती थी। एक दिन धुंध पड़ जाय तो महीनों तक शटल सेवा बंद। कभी सिग्नल प्रणाली तो कभी लॉकिंग-अनलॉकिंग के नाम पर शटल सेवा बंद हो जाती जबकि महंगी वाली ट्रेनें चलती रहती। इस सबके पीछे मोदी का खेल अब सबको समझ आने लगा है कि पहले रेलवे को बर्बाद एवं बदनाम किया जाय फ़िर सुधारने के नाम पर इसे अपने कॉर्पोरेट मित्रों को बेच दिया जाय। स्टेशन बेच दिये जायें। टिकट का पैसा देने के अतिरिक्त स्टेशन प्रवेश का पैसा अलग से वसूला जाय। जाहीर है इस तरह की लूट उन दैनिक यात्रियों से कैसे की जा सकती है जो एमएसटी के लिये महीने भर में 100-200 रुपये देते हैं। ऐसे में उन्हें रेलवे से दूर करना ही होगा।

आईजी प्रॉपर्टी डीलिंग में व्यस्त....

पेज एक का शेष

ताकि जनता को बेहतरीन सुरक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन उनकी आत्मा फरीदाबाद में ही भटकती रहती है। उनका परिवार भी फरीदाबाद पुलिस के ही एक सरकारी आवास में डटा है जिसकी सेवा में हिसार पुलिस की दो गाड़ियां ड्राइवर व सात पुलिसकर्मी तैनात हैं। अपने परिवार से मिलने के बहाने सप्ताह में दो-तीन बार तो आईजी साहब फरीदाबाद में ही रहते हैं। दरअसल यहां इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा भी अच्छा-खासा चल रहा है।

समझने की बात यह है कि जो ऊर्जा व संसाधन संजय कुमार अपने निहित स्वार्थो की पूति हेतु बर्बाद करने में जुटे है यदि उसे अपने क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए खर्च करते तो ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ अपराध तो नियंत्रण में आता। दूसरी चुभने वाली बात यह भी है कि संजय कुमार का सारा कच्चा चिट्ठा प्रदर्शित होने के बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इससे यह समझा जा सकता है कि आईजी संजय जो सरकारी संसाधनों की ऐसी-तैसी करते हुए प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा कर रहे हैं, उसमें खट्टर सरकार एवं गृहमंत्री अनिल विज की स्वीकृति है।

पांच-दस हजार की रिश्वत लेने वाले सिपाही हवलादार को तो सरकार गिरफ्तार कराती फिर रही है और जो खुलेआम मोटी डकैतियां मार रहे हैं उन्हें पूछती तक नहीं। दरसअल खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार को भी तो संजय जैसे कमाऊ पूत की जरूरत रहती है। रही बात सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की तो, कोई एक-आध संजय हो तो सरकार कुछ रोक-टोक भी करे परन्तु यहां तो लगभग सभी संजय बने हुए हैं। ढूढ़ने पर बमुश्किल कोई इक्का-दुक्का अफसर ही मिलेंगे जो सरकारी संसाधनों का बेरहमी से दुरुपयोग नहीं कर रहे। ऐसे में भला खट्टर एवं विज किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं।

कुल मिलाकर आज पुलिस भी दो तरह की बन कर रह गयी है, एक तो वह जिसका काम है लोगों को हर प्रकार की सुरक्षा देना।

इन लोगों में केवल शासक वर्ग से जुड़े लोग ही शामिल रहते हैं, हां सत्ता परिवर्तन के साथ इनमें थोड़ा बहुत हेर-फेर जरूर होता रहता है, दूसरी वह पुलिस है जो लोगों के लुटने, पिटने व मरने के बाद उन्हें अपने कागजात में दर्ज कर लेती है। इन लोगों में वह तमाम निरीह लोग आते है जिसे जनता जनार्दन कहा जाता है और पूरा तंत्र जिसके नाम पर चलाया जाता है। कुछ बेचारे तो इतने बदनसीब बना दिये जाते हैं कि वे तबाह हो चुकने के बावजूद पुलिस कागजात तक में जगह नहीं बना पाते।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि

प्रोफेसर उदयबीर सिंह
5 दिसम्बर 1946-3 अक्टूबर 2020

प्रगतिशील विचारधारा के प्रतिबद्ध विचारक एवम् शिक्षक आन्दोलन के अग्रनि प्रोफेसर उदयबीर सिंह पुत्र श्री केवल सिंह का हैदराबाद में तीन अक्तूबर 2020 शनिवार रात्रि को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान पलवल ज़िले के गांव घरोंट से सम्बन्धित थे। इसलिये उनके व्यक्तित्व पर ग्रामीण परिवेश की गहरी छाप थी।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ से राजनीति विज्ञान में एम.ए.करने के बाद उन्होंने ब्रजमंडल कॉलेज (वर्तमान राजकीय महाविद्यालय), होडल से अध्यापन कार्य शुरू किया। इसके बाद मानसा (पंजाब), तथा सिरसा, टोहना, तावडू, फरीदाबाद तथा गुड़गांव के राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने के बाद वे 31 दिसम्बर 2004 में रिटायर हो गए। प्राइवेट कॉलेज में रहते हुए हरियाणा कॉलेज टीचर्स यूनियन (एचसीटीयू) तत्पश्चात् राजकीय सेवा में आने के बाद गवर्नमैंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (जीसीटीए) के आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई तथा अक्सर गिरफ़्तारी के लिये अपने आप को पेश किया। उनकी मददगार की प्रवृत्ति के कारण वे हमेशा सहयोगियों व विद्यार्थियों में लोकप्रिय रहे।

प्रोफेसर उदयबीर प्रगतिशील अध्ययन केन्द्र, फ़रीदाबाद, नागरिक विचार मंच, हरियाणा तथा अखिल भारतीय प्रगतिशील विचार मंच के आधार स्तम्भ तो थे ही, मज़दूर मोर्चा के संचालन एवं संरक्षण में भी उनका अद्वितीय सहयोग रहा है। उनका निधन मज़दूर मोर्चा परिवार के लिये अपूरणीय क्षति है। वे स्पष्टवादी व सामाजिक व्यक्तित्व के धनी थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिये तैयार रहते थे। उनके भ्रातृतुल्य स्नेहमय व्यवहार तथा शिक्षण जगत व दी संस्कृति कॉर्पोरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, फ़रीदाबाद के प्रधान के रूप में दी गई उनकी निस्वार्थ सेवा, सच्चाई व निष्ठा के लिये उन्हें सदैव याद किया जाएगा। उनका यों अचानक बिछड़ जाने पर मोर्चा परिवार की हार्दिक श्रद्धांजलि।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
2. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
3. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।**
4. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

बहुसंख्यक, सनातनी भीड़ लोकतंत्र के लिये बनती जा रही है चुनौती

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

हाथरस गैंगरेप कांड से भी गंभीर मसला बाबरी मस्जिद पर 30 सितम्बर 2020 को आया अदालती फैसला है, जिसमें बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने में अदालत को संघ परिवार की कोई साजिश नहीं दिखी। मोदी सरकार ने अपने हिन्दुत्व एजेंडे के तहत अदालत, कानून और जांच एजेंसियों का सहारा लेकर तमाम अभियुक्त बरी करवा दिए। लिब्रहान आयोग ने कहा था कि बाबरी मस्जिद पर पूर्व नियोजित हमला था इसके विध्वंस का काम प्रभावकारी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आरएसएस के विशेष प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को सौंपा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 नवम्बर 2019 के निर्णय में कहा था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस स्पष्ट रूप से गैर कानूनी तथा कानून के शासन का घोर उल्लंघन था।

मज़दूर मोर्चा के 4-10 अक्तूबर 2020 के अंक में समकालीन ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। मोदी सरकार के विवादित तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों, आढ़तियों, खेत मज़दूरों तथा विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा देशव्यापी भारी विरोध प्रदर्शन व धरने दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत पूरी मोदी सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इन कानूनों को जायज ठहराने के लिये किसानों को आश्वस्त करने का प्रयास कर रही है कि उन्हें उनकी उपज का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा तथा कोई भी किसान 'एक देश-एक बाजार' की नीति के तहत अपनी उपज पूरे भारत में कहीं भी बेच सकेगा।

'धान की सरकारी खारीद न होने पर किसान भड़के, कई मंडियों में प्रदर्शन', 'सरकार का पोर्टल सिस्टम कर रहा तंग' किसानों की फुर्ती ने मोदी के झूठ की खोली पोल' में मोदी सरकार के झूठ की पोल खोली गई है।

विदित रहे कि उत्तर प्रदेश (यूपी) में गैर बासमती चावल पर तथा हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयानों के बावजूद धान पर न तो किसानों को एमएसपी मिल रहा है और न धान व कपास की पूरी खरीद हो रही है। हरियाणा के करनाल में चावल बेचने आये यूपी के किसानों को हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक कर वापिस भेज दिया।

2017 में यूपी विधान सभा चुनाव प्रचार के समय प्रधान मंत्री मोदी तथा भाजपा ने लड़कियों के बलात्कार को मुद्दा बनाते हुए ''बहुत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार'' नारे लगाकर सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद बलात्कार की घटनाओं की रिपोर्ट आए दिन आ रही हैं, जिनमें बलरामपुर, उन्नाव, कानपुर, हाथरस आदि की घटनाएं प्रमुख हैं।

'बहुसंख्यक, सनातनी भारतीय लोकतंत्र के लिये बनते जा रहे हैं चुनौती' तथा '6 दिसम्बर 1992, यानी न्याय का विध्वंस' में स्वस्थ समाज व्यवस्था व संवेदनशील कानून व्यवस्था स्थापित करने की बजाए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योगी की राजनीति करने में दिलचस्पी का पर्दाफ़ाश किया गया है।

दरअसल दिल्ली दंगों का सच सामने लाने के लिये एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने और दिल्ली पुलिस द्वारा उसे सारे एसओएस कॉल व उसके फॉलोअप, प्रोटेस्ट साइट करने वाले बीट कॉन्स्टेबल की रिपोर्ट, पुलिस पार्टी के साथ गए फोटोग्राफ़र के वीडियोग्राफ़ और फ़ोटोग्राफ़ तथा पुलिस वालों की आपसी कॉल रिकार्ड व ट्रांसक्रिप्ट रिलीज करने की आवश्यकता है।

महान क्रांतिकारी भगत सिंह के जन्मदिवस पर 'लूट, शोषण और अन्याय की व्यवस्था के खिलाफ़ भगत सिंह बन गए हैं नई मशाल' के जरिए क्रांति के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट किया गया है। उनकी क्रांति केवल शासन परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि वे व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें कोइ ऊंच-नीच, छोटा-बड़ा जैसा भेद-भाव न हो।

परंतु आजादी के बाद भी भगत सिंह का सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि विदेशी शासन से राजनैतिक आजादी तो जरूर मिल गई, लेकिन सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का सपना अभी तक अधूरा है। न भूख से आजादी मिली, न आर्थिक, सामाजिक अथवा पितृसत्तात्मक भेद-भाव से आजादी मिली। औपनिवेशिक साम्राज्य की तरह भाजपा की मोदी सरकार भी प्रशासन को चलाने के लिये अदालतों, कानूनी, पुलिस और जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की जांच मोदी सरकार के आधीन दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक दुराग्रह के वशीभूत जांच के बेसिक नियमों की अनदेखी करते हुए पीड़ितों को ही साजिशकर्ता बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। ध्यान रहे कि दंगों की जांच के लिये केन्द्र सरकार ने कोई जांच कमेटी घोषित नहीं की, जिससे यह आशंका प्रबल होती है कि यह सब नियोजित था जिसका 'पुलिस के चार डाक्यूमेंट ही दिल्ली दंगे का सच सामने लाने के लिये काफ़ी है' में सटीक विश्लेषण किया गया है।